नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 05
दि. 05.10.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार का ऐलान: अमित शाह बोले, अब हथियार डालना ही होगा, बातचीत का कोई सवाल नहीं

(जीएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार किसी भी प्रकार की बातचीत के पक्ष में नहीं हैं और नक्सलियों को हर हाल में अपने हथियार डालने होंगे।

जगदलपुर में आयोजित 'बस्तर दशहरा लोकोत्सव' और 'स्वदेशी मेला' के मंच से अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर क्षेत्र को "लाल आतंक" से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ी हैं, और अब यह निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। "अगर कोई अब भी जंगलों में रहकर हिंसा की राह अपनाता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिद और विनाश की ओर बढ़ता कदम है," शाह ने कहा।

गृह मंत्री ने अपने भाषण में बस्तर के आदिवासी समाज से विशेष रूप से अपील की। उन्होंने कहा, "मैं अपने आदिवासी भाइयों और बहनों से कहता हूँ कि वे अपने गाँवों के युवाओं को समझाएँ कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। बंदूक विकास नहीं लाती, वह केवल खून बहाती है। अगर बस्तर को समृद्ध बनाना है, तो युवाओं को हथियार छोड़ने ही होंगे और मुख्यधारा में लौटकर बस्तर के विकास में भागीदार बनना होगा।"

शाह ने इस दौरान यह भी चेताया कि अगर नक्सली संगठन फिर से बस्तर में हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो सुरक्षा बल उन्हें बख्शेंगे नहीं। "सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब बस्तर में केवल शांति और विकास की आवाज़ गूंजेगी," उन्होंने कहा।

कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अमित शाह ने माँ दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देवी से यह प्रार्थना की है कि आने वाले साल 31 मार्च तक सुरक्षा बलों को पूरे बस्तर को 'लाल आतंक' से मुक्त कराने की शक्ति मिले। शाह ने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में भाजपा सरकार के आने के बाद नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है और सुरक्षा बलों ने अब तक 450 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है।

अमित शाह ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही — उन्होंने उस भ्रम को दूर किया जो वर्षों से दिल्ली और कुछ अन्य जगहों में प्रचारित किया जाता रहा है कि नक्सलवाद "विकास की लड़ाई" का परिणाम है। उन्होंने कहा, "यह झूठ है कि नक्सलवाद विकास के लिए लड़ा गया आंदोलन है। असल में, नक्सलवाद ही विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। जिस बस्तर को आज सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही बस्तर नक्सलियों की हिंसा की वजह से दशकों तक पिछड़ा रहा।"

उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर देश की सबसे आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू की है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल आर्थिक सहायता दी जा रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन का अवसर भी दिया जा रहा है। शाह ने बताया कि "सिर्फ एक महीने में 500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो एक नया रिकॉर्ड है।" उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई गाँव नक्सल मुक्त घोषित होगा, उस गाँव के विकास के लिए राज्य सरकार एक करोड़ रुपये की विशेष सहायता देगी।

गृह मंत्री ने इस दौरान बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा 'मुरिया दरबार' में भाग लेकर अपनी खुशी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि "मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस दरबार में बस्तर के सभी जनजातीय समुदायों के प्रमुख नेता मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। यह दरबार 1874 से सक्रिय है और यह केवल न्याय या निर्णय का स्थान नहीं है, बल्कि यह जनसंवाद, आत्मसम्मान और सामाजिक एकता की मिसाल है। मैं दिल्ली जाकर सभी से कहूँगा कि वे जीवन में एक बार बस्तर का मुरिया दरबार अवश्य देखें।"

कार्यक्रम के अंत में अमित शाह ने राज्य सरकार की "महतारी वंदन योजना" की 20वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 65 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपये सीधे स्थानांतरित किए गए। उन्होंने बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में "मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना" का शुभारंभ भी किया, जिससे दुर्गम आदिवासी इलाकों में आवाजाही आसान होगी और ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

ट्रेन और ऊर्जा नेटवर्क पर रूस का भीषण हमला : 30 घायल, 50 हज़ार घर अंधेरे में डूबे

(जीएनएस)। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध ने एक बार फिर से नागरिकों को सीधा निशाना बना दिया है। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। एक रेलवे स्टेशन पर हुई इस बमबारी में कम से कम 30 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को "क्रूर" और "नागरिकों को आतंकित करने वाला" बताया। उनका कहना है कि रूसियों को पता था कि वे यात्री और रेलवे कर्मचारियों पर वार कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें ट्रेन के डिब्बे आग की लपटों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। रेलवे नेटवर्क यूक्रेन के युद्धकालीन ढांचे में बेहद अहम है, क्योंकि इसी से सैनिकों और राहत सामग्री का परिवहन किया जाता है। यही कारण है कि संघर्ष की शुरुआत से रूस लगातार रेलवे लाइनों को निशाना बना रहा है। सुमी में यह हमला रूस की सीमा से महज़ 50 किलोमीटर दूर हुआ, जिससे यूक्रेनी सुरक्षा की कमजोर कड़ी भी उजागर हुई। इसी हमले के साथ रूस ने एक और रणनीतिक वार किया और यूक्रेन के

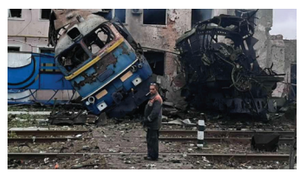

ऊर्जा नेटवर्क को तहस-नहस करने की कोशिश की। चेरनिहिव शहर में ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण करीब 50,000 घर अंधेरे में डूब गए। रात भर चली मिसाइल और ड्रोन बौछार के बाद कई जगह आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूस का असली मकसद ठंड के मौसम से पहले यूक्रेनियों को बिजली, गर्माहट और पानी से वंचित करना है।

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक रूस ने 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागीं। इनमें से बड़ी संख्या में हमले सीधे नागरिक ढांचे पर किए गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 73 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन जो बचे, उन्होंने भारी नुकसान पहुँचाया। इससे पहले रूस ने नाफ्तोगाज, यूक्रेन की सबसे बड़ी गैस कंपनी, की सुविधाओं पर भी हमला किया था।

प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने रूस पर आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर नागरिकों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं रूस का कहना है कि उसके हमले कीव की युद्ध-समर्थक सुविधाओं को नष्ट करने के लिए हैं।

गौरतलब है कि फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध में रूस हर साल सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली आपूर्ति पर हमले करता रहा है। इसका सीधा उद्देश्य लोगों को कठिन परिस्थितियों में डालकर उनकी सरकार और युद्ध के प्रति समर्थन को कमजोर करना है। इस बार उसने रेलवे और ऊर्जा दोनों नेटवर्क पर एक साथ वार किया है, ताकि यूक्रेन के सैन्य और नागरिक जीवन को एक झटके में पंगु किया जा सके।

इस हमले के बाद साफ है कि युद्ध थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन अपने ढांचे को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। सर्दियों के आगमन से पहले यूक्रेन की जनता के सामने अंधेरा, ठंड और भय—तीनों की त्रासदी एक साथ खड़ी हो गई है।

मणिपुर में बड़ा ऑपरेशन: तीन जिलों से 10 उग्रवादी गिरफ्तार, असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क को करारा झटका

(जीएनएस)। मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों में तीन जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े दस उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन अभियानों को मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

असम राइफल्स के अधिकारियों के अनुसार, चुराचांदपुर जिले में 'ऑपरेशन सोंगकोट' के तहत जंगलों में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) से जुड़े छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार व्यक्तियों में संगठन का वरिष्ठ कमांडर एसएस लेफ्टिनेंट जामखोगिन गुइते लुफो, जो 'पेप्सी' नाम से जाना जाता है, भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया।

सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, यूकेएनए का यह नेटवर्क चुराचांदपुर और जिरीबाम जिलों में सक्रिय था और यह पिछले कुछ महीनों में कई हिंसक घटनाओं में शामिल पाया गया था। असम राइफल्स के जवानों ने जंगलों में कई ठिकानों को खंगाला, हथियार और गोला-बारूद बरामद किए, और संगठन के कई

ठिकाने ध्वस्त किए। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से यूकेएनए के नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगा है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों पर रोक लगी है।

गिरफ्तार कमांडर जामखोगिन गुइते लुफो के बारे में बताया गया है कि वह जनवरी 2024 में बिष्णुपुर जिले में हुई एक सनसनीखेज हत्या की वारदात में मुख्य आरोपी था। इस घटना में मैतेई समुदाय के चार लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें एक पिता और उसका पुत्र भी शामिल था। यह घटना उस समय की थी जब मणिपुर में जातीय हिंसा अपने चरम पर थी। अधिकारियों ने कहा कि इस गिरफ्तारी से उस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और आगे की जांच से कई और कड़ियाँ खुलने की संभावना है।

वहीं, दूसरी ओर मणिपुर पुलिस ने भी थौबल और इंफाल जिलों में एक अलग कार्रवाई कर चार अन्य उग्रवादियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार, थौबल जिले में प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुनबा) से जुड़े दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। यह संगठन लंबे समय से राज्य में वसूली, धमकी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है।

इंफाल पश्चिम जिले के निंगोमबाम इलाके से पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का एक स्वयंभू कॉर्पोरल और नाओरेमथोंग से कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्ल्यूजी गुट) के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इनसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, मोबाइल संचार रिकॉर्ड और संगठनात्मक सामग्री बरामद हुई है, जिससे कई नेटवर्क की कड़ियाँ उजागर होंगी।

मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भड़क उठी जातीय हिंसा ने राज्य को गहरे संकट में डाल दिया था। इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। सरकार ने हाल के महीनों में राज्य में शांति बहाल करने और उग्रवादी संगठनों को समाप्त करने के लिए सैन्य और पुलिस अभियानों की तीव्रता बढ़ाई है।

अधिकारियों का कहना है कि इन हालिया गिरफ्तारियों से उग्रवादी नेटवर्क कमजोर पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर भय और अस्थिरता के वातावरण में कमी आएगी। सुरक्षा एजेंसियाँ मानती हैं कि जब तक इन प्रतिबंधित संगठनों की वित्तीय और रसद आपूर्ति को पूरी तरह काट नहीं दिया जाता, तब तक राज्य में स्थायी शांति संभव नहीं होगी।

मणिपुर के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारा उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि उन ताकतों को समाप्त करना है जो हिंसा के जरिए समाज को बाँटने की कोशिश कर रही हैं। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस का संयुक्त अभियान इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।"

इन गिरफ्तारियों के बाद राज्य में सुरक्षा बलों ने चौकसी और बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी मजबूत की गई है और संवेदनशील गाँवों में गश्त बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी और जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, उन्हें मुख्यधारा में लौटने के लिए सभी संभव अवसर दिए जाएंगे। मणिपुर में चल रहा यह सुरक्षा अभियान अब केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की सामाजिक एकता और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इन दस उग्रवादियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी सशस्त्र संगठन को राज्य की शांति में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगी।

यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करने का निर्णय लिया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट किया कि अब वह प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने के बाद अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करेगा। यह निर्णय सिविल सेवा परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हलफनामे में यूपीएससी ने बताया कि यह कदम एक लंबित याचिका के संदर्भ में उठाया गया है, जो सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र के सुझावों के साथ ही अन्य कारकों पर भी विचार-विमर्श किया। वकील वर्धमान कौशिक ने बताया कि इस निर्णय में यूपीएससी की संवैधानिक जिम्मेदारी और उम्मीदवारों के हित दोनों का ध्यान रखा गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करने का उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम और अंकांकन के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी देना है। इससे उम्मीदवार अपनी तैयारियों

और भविष्य की रणनीति का आकलन कर सकेंगे।

यूपीएससी की यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाली मानी जा रही है। आयोग ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में इसी प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे, ताकि उम्मीदवारों को समय पर सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

इस निर्णय से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों में विश्वास और संतोष बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा के बाद प्रारंभिक उत्तरों की पुष्टि करने का अवसर मिलेगा। यह कदम उम्मीदवारों और आयोग दोनों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महाराष्ट्र में ओबीसी संगठनों ने श्वेत पत्र की मांग की, फडणवीस के साथ बैठक में उठे मुद्दे

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शनिवार को सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संगठनों ने मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने वाले सरकारी आदेश का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। ओबीसी संगठनों का कहना था कि यह आदेश 2 सितंबर को जारी किया गया था और उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि आदेश मनोज जरांगे के नेतृत्व में पांच दिवसीय आंदोलन के बाद जारी किया गया, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते।

बैठक में ओबीसी संगठनों ने 2014 से अब तक राज्य में जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों और जाति वैधता प्रमाणपत्रों पर पारदर्शिता और कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए 'श्वेत पत्र' प्रकाशित करने की भी मांग की। उनका मानना है कि श्वेत पत्र से प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होगी और जातिगत विवादों को रोका जा सकेगा। बैठक में शामिल कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्यव्यापी ओबीसी रैली 10 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी दो प्रमुख मांगों—सरकारी आदेश को वापस लेना और श्वेत पत्र प्रकाशित करना—पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं

दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार कानूनी ढांचे के भीतर हर समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है और प्रमाणपत्रों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रणाली और वंशावली समिति बनाई गई है। फडणवीस ने यह भी बताया कि इस महीने 'महाज्योति' योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं और राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए कुल 63 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी एक समुदाय को आरक्षण मिलने से अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन नहीं होगा और सभी निर्णय कानून के दायरे में होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झूठे दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दवा या ज़हर : बच्चों की मौत से हड़कंप और सरकारों की ताबड़तोड़ कार्रवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश भर में पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल गूंज रहा है—क्या बाज़ार में आसानी से मिलने वाली खांसी की दवा, जो बच्चों को राहत देने के लिए दी जाती है, वास्तव में दवा है या ज़हर? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कफ सिरप पीने के बाद मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। घटनाओं की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दवाओं में ऐसा जहरीला रसायन मिला है, जो मानव शरीर के लिए घातक है और जिसने बच्चों की किडनी फेल कर दी।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से शुरुआत हुई, जहां 27 दिन के भीतर 10 बच्चों की मौत हो गई। शुरुआत में मामला सामान्य बीमारी और किडनी फेल होने का माना गया, लेकिन जब मौतों का सिलसिला एक के बाद एक जारी रहा तो स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। जांच में सामने आया कि जिन बच्चों को खांसी-जुकाम के लिए कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था, उनमें अचानक किडनी फेल होने लगी। नमूनों की जांच के बाद पाया गया कि दवा में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) मौजूद था। इसकी मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक थी। DEG का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है—पेंट, ब्रेक फ्लूड और एंटीफ्रीज़ में। यह मानव शरीर में पहुंचकर ज़हर की तरह असर करता है। बच्चों का शरीर इस ज़हर को झेल

नहीं पाया और मौत हो गई।

राजस्थान के भरतपुर और सीकर ज़िलों से भी ऐसी ही खबर आई। यहां डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप देने के बाद दो बच्चों की मौत हुई। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मौत की वजह किडनी फेल होना थी और सिरप का सेवन ही इसका कारण बना। इसके बाद सरकार हरकत में आई और जयपुर स्थित केसंस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर को भी निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी। इसने राज्य की दवा निगरानी व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया।

तमिलनाडु में भी उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई। यहां दवा के बैच नंबर SR-13 की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें DEG की मात्रा 48.6% थी। यानी दवा में लगभग आधा हिस्सा जहरीले रसायन का था। इसे देखकर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और फैक्ट्री का उत्पादन रुकवा दिया।

इन घटनाओं ने देशभर में सनसनी फैला दी। जब-जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोगों का भरोसा दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं से उठने लगता है। सवाल उठता है कि जब दवा बाजार में पहुंचती है तो क्या उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती? अगर होती है तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है?

केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने छह राज्यों में 19 दवा कंपनियों के प्लांट की जांच शुरू की। उद्देश्य साफ था—ऐसी खामियों की पहचान करना और यह देखना कि आखिर किन लापरवाहियों की वजह से बच्चों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की। उसमें स्पष्ट कहा गया कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हाल में कफ सिरप न दिया जाए। पांच साल तक के बच्चों को भी सामान्यतः यह दवा न दी जाए। अगर कभी डॉक्टर ज़रूरी समझकर देते हैं तो बच्चे को कड़ी निगरानी में रखा जाए, न्यूनतम खुराक और सीमित दिनों तक ही दवा दी जाए।

यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम दवा की आड़ में बच्चों को ज़हर पिला रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप का उपयोग लंबे समय से होता आया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे पहले से ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसका कारण यही है कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट बच्चों पर बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अब सरकारों की कार्रवाई से भले ही उत्पादन और बिक्री पर रोक लग गई हो, लेकिन जिन परिवारों ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, उनके लिए यह कदम बहुत देर से आया है। वे हमेशा यही सोचेंगे कि अगर निगरानी पहले कड़ी होती, तो उनके बच्चे आज ज़िंदा होते। यह त्रासदी भारत की दवा व्यवस्था और नियामक संस्थाओं के लिए आईना है, जो यह बताती है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उसके सख्त पालन की ज़रूरत है।

दवा और ज़हर के बीच का फर्क बहुत पतला है। वही दवा जो किसी को राहत दे सकती है, वही दवा ज़रा-सी लापरवाही के कारण मौत का कारण बन सकती है। बच्चों की इन मौतों ने यह साफ कर दिया है कि अब सरकार और समाज दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा का नाम लेकर किसी को ज़हर न पिलाया जाए।

संपादकीय

दवा कंपनियों की जिम्मेदारी तय हो

कैसी विडंबना है कि जीवन रक्षा के लिये दी जाने वाली दवा मौत का कारण बन जाए। जो दवा की संदिग्ध गुणवत्ता और निर्माता कंपनियों की आपराधिक लापरवाही को ही उजागर करती है। जाहिर है रसायनों की घातकता की मात्रा और गुणवत्ता में कोई खोट इस तरह के हादसों का सबब बना होगा। राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की वजह का संबंध उस सिरप से बताया जा रहा है, जो खांसी ठीक करने के लिये दिया गया। ये हादसे इस बात को रेखांकित करते हैं कि दवा की गुणवत्ता में चूक सामान्य उपचार को कितने जानलेवा जोखिम में बदल सकती है। बताया जाता है कि बच्चों को कथित रूप से मुख्यमंत्री की मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में एक जेनेरिक खांसी की सिरप दी गई थी। जबकि इस मामले में जांच चल रही है, यह त्रासदी भारत की फार्मास्यूटिकल निगरानी तंत्र की कोताही ही उजागर करती है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो फार्मा हब के रूप में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 655 फार्मास्यूटिकल इकाइयों में से केवल 122 ही जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के संशोधित शेड्यूल एम मानकों के तहत अपग्रेड करने के लिये पंजीकृत हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश फार्मा इकाइयां गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को प्रमाणित किए बिना काम कर रही हैं। ये जनस्वास्थ्य के प्रति कितनी गैरजिम्मेदार स्थिति है। जबकि हकीकत यह है कि फार्मास्यूटिकल इकाइयों को अपग्रेड करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। यह नियामक तंत्र की कमजोरियों और छोटी फर्मों में सुरक्षित प्रक्रियाओं में निवेश करने की अनिच्छा को ही उजागर करती है। यह विडंबना ही है कि हमारा तंत्र जन-स्वास्थ्य के खिलवाड़ के प्रति उदासीन बना हुआ है। निस्संदेह, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके लिये यह बहस कोई सांत्वना नहीं है। उन्हें सही मायनों में सांत्वना तभी मिलेगी जब आपराधिक लापरवाही करने वालों को दंडित किया जाएगा।

विडंबना यह है कि अतीत में भी ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं, लेकिन हमारे तंत्र ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं दी जाएं। वर्ष 2020 में भी एक ऐसी त्रासदी सामने आई थी, लेकिन कुछ दिन के शोर के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विडंबना देखिए कि मृत बच्चों के परिजन आज भी न्याय की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसी मौतों की जिम्मेदारी तय करने में लगातार देरी होती रहती है। ऐसे हादसों को या तो कमतर दर्शाया जाता है या फिर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विगत में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। भारत की फार्मा कंपनियों के द्वारा तैयार सिरप से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का लिंक पाए जाने के बाद भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। निस्संदेह, ऐसे गैर-जिम्मेदार तरीके से तैयार दवाइयों के चलते भारत की 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में हासिल प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा है। हमारे नियामक तंत्र को और कितने बच्चों के मरने का इंतजार है.. जरूरी है इससे पहले गुणवत्ता नियंत्रण सिर्फ कागज पर नहीं व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने दवाइयों के गुणवत्ता मानकों को तय करने के लिए सख्त तरीके जीएमपी अनुपालन हेतु समय-समय पर निरीक्षणों के लिये कदम उठाए हैं। लेकिन प्रवर्तन के स्तर पर अभी भी तमाम खामियां बरकरार हैं। विडंबना यह है कि राज्य नियामकों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। साथ ही अकसर दंड के प्रावधान प्रभावी नहीं होते। यह एक कटु सत्य है कि भारत की फार्मा सफलता की कहानी केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयों पर आधारित नहीं रह सकती। हमें इसे विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। इसके लिए मजबूत ऑडिट, लापरवाही के लिए आपराधिक जिम्मेदारी तय हो और मामलों में पीड़ितों को तीव्र न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा, ऐसी हर त्रासदी जन-विश्वास को कमजोर करती है- जो किसी भी दवा में सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

तबाही का सबब बन सकती हैं ग्लेशियर झीलें

> वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर झीलों का तेजी से विस्तार भविष्य में 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी आपदाओं का कारण बन सकता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 13 बेहद खतरनाक और 5 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। कई झीलें मौसम व भौगोलिक कारणों से बनती-बिगड़ती रहती हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में नई ग्लेशियर झील के आकार में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियर झीलों की संख्या और आकार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि निचले इलाकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, क्योंकि इन झीलों के टूटने से बाढ़ जैसी आपदाएं आ सकती हैं। उच्च हिमालय में झीलों का यह विस्तार वैज्ञानिकों और प्रशासन दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर झीलों का तेजी से विस्तार भविष्य में 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी आपदाओं का कारण बन सकता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 13 बेहद खतरनाक और 5 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। कई झीलें मौसम व भौगोलिक कारणों से बनती-बिगड़ती रहती हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में नई ग्लेशियर झील के आकार में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।

केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अरुणाचल में 197 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। ये अपना खतरनाक स्तर पर विस्तार कर रही हैं। इनके बाद लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड में झीलें हैं। एनडीएमए ने उत्तराखंड की इन खतरनाक 13 झीलों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पिछले दिनों में गंगोत्री की केदारताल और चमोली में वसुतारा झील का काफी विस्तार हुआ है। इन झीलों के गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. एम.पी.एस. बिष्ट द्वारा वर्ष 2014 और 2023 के उपग्रह चित्रों के अध्ययन से यह चिंताजनक खुलासा हुआ है। उनके मुताबिक ये झीलें हिमनद के असंगठित मलबे—मोराइन डैम की

रुकावट से बनी हैं। उनका मानना है कि इस खतरे को देखते हुए सरकारों और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को समय रहते इन झीलों का आकलन कर तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। वास्तव में उत्तरकाशी की धराली की घटना ने उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों के बढ़ते खतरे को फिर से चर्चा में ला दिया है।

वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान चौराबाड़ी ग्लेशियर झील के फटने से हुई तबाही ने ग्लेशियर झीलों के खतरे को गंभीर मुद्दा बना दिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 968 ग्लेशियर और कई हजार ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। इन झीलों में अत्यधिक बर्फ पिघलने से अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता है। इन झीलों का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका लगातार बनी रहती है।

हकीकत यह है कि मौसम के इस बदलते पैटर्न के बारे में बहुत कुछ समझना अभी भी बाकी है। इसलिए पिछले तकरीबन तीस सालों के आंकड़ों का गहनता से आकलन बेहद जरूरी है। आपदाओं के पूर्वानुमान को भी बेहतर बनाना समय की मांग है। यही नहीं, आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिमालय के जटिल और प्राचीन भूभाग पर कार्बन युक्त एरोसोल के अध्ययन को नजरंदाज करना बहुत बड़ी चूक होगी।

अध्ययन में खुलासा हुआ है कि हिमालय में वायु प्रदूषण में जीवाश्म ईंधन के जलने का ज्यादा असर पड़ रहा है। हिमालय अंचल में गाड़ियों की बढ़ती तादाद हवा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का अहम कारण है। हिमालयी बस्तियों और शहरों के बढ़ते बोझ से अब हांफने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर पिघलकर बनी झीलें जल प्रलय को आमंत्रण दे रही हैं। इसरो की मानें तो हिमालय क्षेत्र की 2432 ग्लेशियर झीलों में से 672 झीलों का तो आकार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इनमें से भारत में मौजूद 130 झीलों के टूटने का खतरा हमेशा बना हुआ है।

इसमें दो राय नहीं कि दिनोंदिन बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की आंधी ग्लेशियरों के विनाश का सबब बन रही है। समुद्र के जलस्तर में वर्ष 1900 की तुलना में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी और उसमें हो रही दिन-ब-दिन तेजी से वृद्धि, जिसके चलते कुछ द्वीप और तटीय इलाके डूबते जा रहे हैं। कुछ महानगरों-शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है, बाढ़ की विनाशलीला बस्तियों को लील रही है, वहीं सूखा गांवों को वीरान बनाने की राह पर है। ऐसी विषम स्थिति में ग्लेशियरों को बचाना महज बर्फ को बचाना नहीं है बल्कि अपने भविष्य को बचाना है।

वैज्ञानिकों के शोध-अध्ययन इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में ग्लेशियर झीलों में बहुतेरी ऐसी हैं जिनका आकार जून, 2025 के दौरान बढ़ा है। याद रखना होगा कि ग्लेशियर मात्र बर्फीले शिखर ही नहीं हैं, वे हमारे भविष्य की जड़ें हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि बर्फ के पिघलने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र बदल जाता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है।

इन बढ़ते खतरों से निपटने की दिशा में हमें तत्काल कार्रवाई, फंडिंग के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में मानवीय दखलंदाजी पर अंकुश, जलवायु परिवर्तन के दानव और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगानी ही होगी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हिमालय की जल धाराएं मौन हो जाएंगी, हम बूंद-बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे, खेत सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। आपदा प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन जागरूकता, सतर्कता और सावधानी से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं।

प्रेरणा

गति की शक्ति: हार से जीत तक एलिजाबेथ की अमर

पंद्रह साल की एक साधारण-सी दिखने वाली किशोरी, एलिजाबेथ, हर दिन स्कूल से घर लौटने के लिए तेज़ी से ट्रेन पकड़ती थी। लेकिन उस दिन की हड़बड़ी ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसके अध्यापक चार्ल्स प्राइज उसकी गति देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इस लड़की में कुछ असाधारण है। उन्होंने स्टॉपवॉच निकाली, उसकी गति नापी, और यह जानकर चकित रह गए कि उसकी दौड़ने की रफ्तार किसी प्रशिक्षित खिलाड़ी से कम नहीं।

चार्ल्स ने एलिजाबेथ को बुलाया और कहा, "तुम सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रही हो, तुम जीवन की एक दिशा पकड़ रही हो। तुम्हें इस प्रतिभा को सँवारना होगा।" उस दिन से उन्होंने एलिजाबेथ को प्रशिक्षण देना शुरू किया। साधारण जूतों में, धूल भरे मैदानों में, बिना किसी आधुनिक सुविधा के, वह हर दिन अभ्यास करने लगी। उसकी आंखों में चमक थी, एक विश्वास कि वह दुनिया को अपनी गति से चकित कर देगी।

कुछ ही महीनों में उसने स्थानीय और फिर घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहाँ उसका सामना हुआ अमेरिकी चैंपियन हेलेन फिल्की से—जो 100 मीटर रेस की सर्वश्रेष्ठ धाविका मानी जाती थी। वह

मुकाबला एलिजाबेथ के लिए निर्णायक साबित हुआ। हालांकि वह दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जिसने उसे दौड़ते देखा, जान गया कि यह लड़की आगे चलकर इतिहास लिखेगी।

तीन महीने बाद फिर वही मुकाबला हुआ—इस बार एलिजाबेथ ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। उसने हेलेन फिल्की को पछाड़ दिया और देश की नई चैंपियन बन गई। अब उसकी नजर एम्सटर्डम ओलंपिक पर थी। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और जिद्द के साथ उसने क्वालीफाई किया। वह अमेरिका की इकलौती धाविका बनी जिसने 100 मीटर रेस में जगह बनाई। और जब एम्सटर्डम में उसने ट्रैक पर कदम रखा, तो मानो हवा थम गई। फिनिश लाइन पार करते ही एलिजाबेथ इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी—सोलह वर्ष की उम्र में वह पहली अमेरिकी महिला बनी जिसने 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड जीता।

लोग उसे "बेट्टी रॉबिन्स" के नाम से जानने लगे। अख़बारों ने लिखा—"यह लड़की हवा से भी तेज़ दौड़ती है।" लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। 1931 के जून महीने में एलिजाबेथ अपने भाई के साथ उसके छोटे विमान में उड़ी। आसमान में 600 मीटर की ऊंचाई पर विमान अचानक क्रैश हो गया। गिरते हुए मलबे से धुआं उठा और नीचे लोग दौड़ पड़े। जब बचाव दल पहुँचा, तो दोनों अचेत थे। एलिजाबेथ को देखकर डॉक्टरों ने सिर हिलाया—उसकी टांगें और बाहें बुरी तरह टूट चुकी थीं, और उन्होंने कह दिया कि अब वह जीवनभर चल भी नहीं सकेगी।

लेकिन वह लड़की जो कभी हार मानना नहीं जानती थी, उसने दर्द को अपनी चुनौती बना लिया। महीनों तक अस्पताल में पड़ी रही, हड्डियाँ जोड़ते हुए आँसू बहाए, पर मन में सिर्फ एक विचार था—"मैं फिर दौड़ूंगी।" डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद उसने बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया। उसकी चाल डगमगाती थी, लेकिन हौसला अटल था। धीरे-धीरे उसने चलना सीखा, फिर दौड़ना, और अंततः फिर वही ट्रैक उसका इंतजार कर रहा था जहाँ से उसने शुरुआत की थी।

चार साल की यातना, धैर्य और असंभव पर विश्वास के बाद, वह एक बार फिर ओलंपिक ट्रैक पर लौटी। 8 अगस्त 1936, बर्लिन ओलंपिक—जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह टूटी हुई हड्डियों वाली वह लड़की फिर से हवा से बातें कर रही है। उसने न केवल दौड़ पूरी की, बल्कि स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया।

एलिजाबेथ, यानी बेट्टी रॉबिन्स, ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति शरीर की नहीं, मन की होती है। जो व्यक्ति अपने विश्वास की गति से दौड़ता है, उसके लिए कोई बाधा, कोई दर्द, कोई हादसा अंतिम नहीं होता। उसकी कहानी आज भी बताती है—

"गति की असली शक्ति पैरों में नहीं होती, आत्मा में होती है।"

अमेरिकी अविश्वास से बनते नए कूटनीतिक समीकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या विश्व कूटनीति में नये समीकरण उभर रहे हैं, नई दोस्तियां हो रही हैं, नए समझौते हो रहे हैं इनके केंद्र में पश्चिमी एशिया व एशिया है, जहां के देशों के बीच पुनर्मिलन व नई संरचनाएं हो रही हैं। इसमें से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आकार ले सकता है। विश्व व्यापार में जी-7 देशों का दबदबा कम होना और जी-20 का प्रभाव बढ़ना क्या इसका सूत्रधार है।

ये तमाम सवाल ट्रंप के रोज नए पैंतरों और उनके जवाब में देशों के झुकने के बजाय नये रास्ते निकालने से और तेज हो गये हैं। इसके एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता दिखाई देता है। जिस तरह से ये दोनों देश—जो अमेरिका के साथ ही माने जाते हैं, वे साथ आए, उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मची है। सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया के देशों में खासतौर से जो अमेरिका की गुड बुक्स में रहे हैं, उनका भरोसा अमेरिका से हट रहा है। पश्चिम एशिया के देश क्या अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसे ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान के तालिबानी शासन पर बगराम एयरबेस को वापस मांगने के लिए धमकी देने वाले घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से तालिबानी शासन ट्रंप की इस मांग का विरोध कर रहा है—वह उसके वर्चस्व को चुनौती देने जैसा प्रतीत होता है। और तो और ट्रंप ने भारत पर जो एच1बी वीजा की फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपये सालाना करके एक और वार किया, उसमें चीन का के-1 वीजा का ऑफर भी इसी सिलसिले में दिखाई देता है।

आखिर पश्चिमी एशिया में ऐसा क्या घट रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इतना अहम समझौता किया। दरअसल, इस समझौते के पीछे सबसे बड़ा कारक है कतर पर किया गया इस्राइल का हमला। जिस तरह से इस्राइल ने अच्छी-खासी दूरी को लांघते हुए कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया—उसने पूरे इलाके में गहरा विक्षोभ व असंतोष पैदा किया। कतर अमेरिका का पुराना सहयोगी देश है और यहां वर्ष 2000 से अमेरिका का सैन्य अड्डा है। कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ते एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। यानी कतर को यह 100 फीसदी गारंटी थी कि अमेरिका का सैन्य अड्डा यहां है, लिहाजा वह इस्राइल समेत तमाम देशों के किसी भी हमले से महफूज़ है। जब दोहा में हमास के नेताओं को मारने के लिए इस्राइल ने हमला बोला—तब उसका ये विश्वास खंडित हो गया। यहां कतर का यह कहना भी वाजिब है कि वह अमेरिका के कहने पर ही फलस्तीन के मिलिटेंट संगठन हमास के संग शांति वार्ता आयोजित कर रहा था ऐसे में उसकी राजधानी पर इस्राइल का हमला—उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पूरे इलाके में खलबली मची। साथ ही साथ सऊदी अरब को भी लगा कि वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस्राइल की मिसाइलें सऊदी के एयर स्पेस को पार करके ही दोहा पहुंच सकती थीं। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में बड़ा देश है और उसे भी गहरी बेचैनी व असुरक्षा लगी। वरना, अभी तक ये सारे देश (मुस्लिम देश) विश्व कूटनीति में अमेरिका के साथ ही माने जाते रहे हैं।

इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक तरह से कतर को उसकी औकात बताने के लिए कहा कि उन्होंने ट्रंप को दोहा पर इस हमले के बारे में बता दिया था। यानी इस्राइल ने अपनी बॉसगीरी को छुपाकर नहीं रखा और यह भी कह दिया कि वह आगे भी ऐसा ही करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी मजबूरी में कहना पड़ा कि इस्राइल सही कह रहा है। सऊदी अरब जो इस इलाके का सबसे बड़ा और शक्तिसंपन्न देश है, उसने गहरी असुरक्षा से भरकर ही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया।

इस लिहाज से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता, इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसमें तय किया गया है कि यदि किसी बाहरी देश ने एक पक्ष पर आक्रमण किया तो इसे दूसरे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्ब्रेला के अंदर है, यानी पाकिस्तान द्वारा सऊदी के रक्षा कवच के रूप में न्यूक्लियर क्षमताएं शामिल हो सकती हैं। आज की तारीख में सऊदी अरब के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कवच मौजूद होगा, जो उसे किसी भी देश के हमले में बचाने में काम आ सकता है। पाकिस्तान का भी कद बढ़ गया और उसे न्यूक्लियर पॉवर होने का लाभ भी मिला।

हालांकि, यह कहना अभी दूर की कौड़ी होगी कि इससे क्या पश्चिम एशिया में अमेरिकी पकड़ ढीली होगी, क्योंकि बड़ा प्लेयर अभी भी अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती जरूर मिल रही है। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र परिषद में गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर भी अमेरिका अलग-थलग पड़ गया था। भारत में शंघाई सहयोग संगठन के प्रस्ताव के बाद यहां भी सीजफायर यानी गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में अपना मत दिया था।

वैसे यह याद रखना भी जरूरी है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच यह समझौता भारत के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इसकी वजह साफ है कि यह समझौता पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली राज्य के साथ एक पारंपरिक रक्षा साथ जोड़ता है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत को पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक पहुंच और साझेदारियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान वास्तव में सऊदी को न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रदान करता है तो भारत के परमाणु रणनीतिक पर यह एक नया तत्व जोड़ता है। भारत को यह देखना होगा कि इस तरह की स्थिति में कौन-सी कार्रवाई और सुरक्षा नीति अपनानी है।

अभियान

श्रीराम जन्म का दिव्य रहस्य और जय-विजय की कथा

भगवान शंकर जब माता पार्वती को श्रीराम जन्म का प्रसंग सुनाने लगे तो उनके मुख से जो कथा निकली वह दिव्य भी थी और गहन रहस्यों से भरी हुई भी। उन्होंने कहा कि श्रीराम का अवतार किसी एक कारण से नहीं हुआ। ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो उसके पीछे अनेक अद्भुत कारण होते हैं जिन्हें मनुष्य बुद्धि से पूरी तरह समझ पाना असंभव है। रामावतार भी एक गूढ़ लीला का परिणाम था।

महादेव बोले—हे भवानी! मैं राम जन्म के सभी कारणों का गान करने में असमर्थ हूँ। क्योंकि उनकी लीला अपार और अगम्य है। किंतु तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं उनके जन्म से जुड़े कुछ विशेष कारण अवश्य कहूँगा।

सबसे पहले महादेव ने जय और विजय की कथा सुनाई। ये दोनों भगवान विष्णु के परम प्रिय द्वारपाल थे। वैकुण्ठ धाम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ये सोचते थे कि वे स्वयं भी प्रभु के समान महत्त्वपूर्ण हैं। धीरे-धीरे उनके हृदय में यह अहंकार घर करने लगा कि वे जिसे चाहें, उसे भगवान विष्णु के दर्शन से रोक सकते हैं।

एक दिन सनक, सनंदन, सनातन

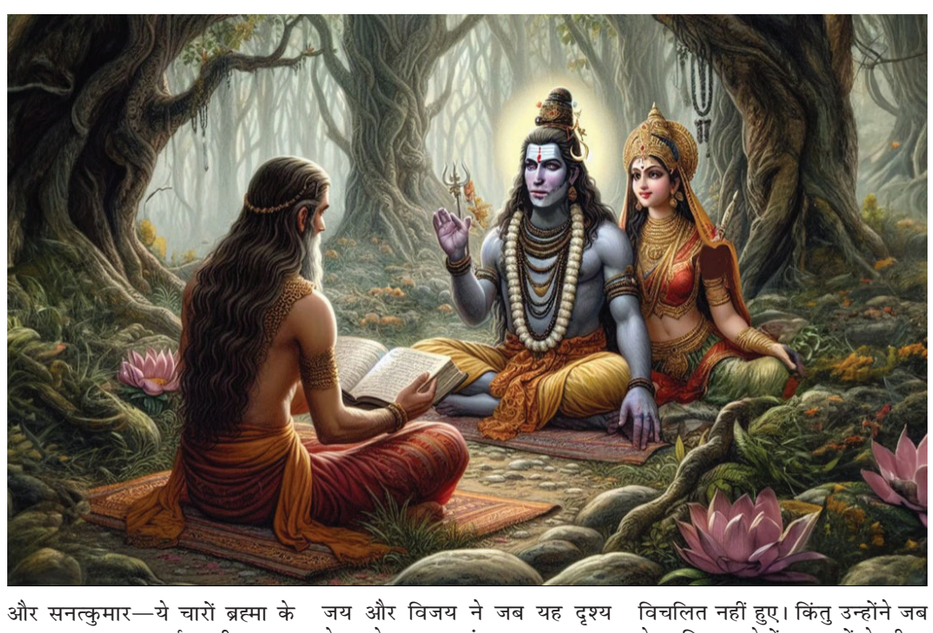

और सनत्कुमार—ये चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र, प्रभु दर्शन की उत्कट इच्छा लेकर वैकुण्ठ में प्रवेश करने पहुँचे। वे अत्यंत निरहंकारी और प्रभु-प्रेम में लीन थे। इस कारण वे यह भूल ही गए कि द्वार पर कोई रक्षक भी खड़ा है। वे सीधे भीतर जाने लगे।

जय और विजय ने जब यह दृश्य देखा तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि इन ऋषियों ने उनका अपमान किया है। उन्होंने क्रोध में आकर सनकादि ऋषियों को अपशब्द कहे और भीतर प्रवेश करने से रोका। सनकादि ऋषियों का मन तो समुद्र की तरह शांत था। वे अपशब्दों से विचलित नहीं हुए। किंतु उन्होंने जब देखा कि इन दोनों द्वारपालों के भीतर अहंकार और दुष्टता कूट-कूट कर भरी हुई है, तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा—"तुम दोनों वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति के हो, अतः अगले जन्म में राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लो।"

श्राप मिलते ही जय और विजय के होश उड़ गए। वे रोते-बिलखते भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा माँगने लगे। उस समय स्वयं भगवान प्रकट हुए और बोले—"ऋषियों के वचन अटल हैं। यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। किंतु मेरे सेवक होने के कारण मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जब-जब तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे, तब-तब मेरे ही हाथों से मोक्ष को प्राप्त करोगे।"

भगवान विष्णु के वचनों ने उन्हें सांत्वना दी। अब यह निश्चित हो गया कि जय और विजय तीन बार राक्षस रूप में जन्म लेंगे और हर बार भगवान स्वयं अवतार लेकर उनका उद्धार करेंगे।

पहली बार वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। उस समय भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरी बार वे रावण और कुम्भकर्ण के रूप में जन्मे और तब भगवान ने श्रीराम के रूप में अवतार लेकर इस त्रैलोक्य को उनके आतंक से मुक्त किया। तीसरी और अंतिम बार वे शिशुपाल और दंतवक्र बने और श्रीकृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। रामावतार का रहस्य यहीं से जुड़ता है। जब जय और विजय ने रावण और कुम्भकर्ण का रूप लिया, तब उनके अहंकार और दुष्टता से सम्पूर्ण सृष्टि त्रस्त हो गई। देवता और ऋषि तक उनके अत्याचार से भयभीत थे। पृथ्वी माता स्वयं करुणा से भरकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लें।

इसीलिए भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। रामावतार केवल रावण के वध के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना, आदर्श मर्यादा का प्रदर्शन, सत्य और प्रेम की रक्षा तथा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए था।

महादेव माता पार्वती से कहते हैं—ईश्वर की लीला का रहस्य गहन है। एक ओर यह ऋषियों के श्राप और जय-विजय के अहंकार से जुड़ा है, तो दूसरी ओर भक्तों की पुकार और सृष्टि की रक्षा से। श्रीराम के जन्म की यह कथा वास्तव में यह सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता के हृदय में ही क्यों न आ जाए, अंततः वह पतन का कारण बनता है। और जब-जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

ठाणे में 530 लिपिक-टाइपिस्टों की अनुकंपा नियुक्ति, जिलाधिकारी ने ईमानदारी और जिम्मेदारी का संदेश दिया

(जीएनएस)। ठाणे। ठाणे ज़िले में अनुकंपा के आधार पर 530 लिपिक-टाइपिस्टों की नियुक्ति का ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें और महाराष्ट्र को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के सपने में योगदान दें। यह समारोह ज़िला योजना समिति हॉल में हुआ, जिसमें अनुकंपा और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

समारोह में विधायक संजय केलकर, विधायक सुलभा गायकवाड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त आदिवासी विकास परियोजना आयुक्त गोपीचंद कदम, पुलिस अधीक्षक डॉ. डी. स्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त उम्मीदवार उपस्थित थे। समारोह का मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य राज्य रोजगार मेले से भी सीधा प्रसारण किया गया।

जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि अनुकंपा के तहत यह निर्णय 45 सरकारी मामलों पर विचार करने के बाद लिया गया। दस्तावेज़ सत्यापन जैसी जटिल प्रक्रिया केवल दो से ढाई महीने में पूरी की गई। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग और मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को पूरी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने नए पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और लगन से निभा सकें।

राज्य में एक ही दिन में इतने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना एक रिकॉर्ड जैसा रहा। ठाणे ज़िला नियोजन भवन में ग्रुप सी में 98, ग्रुप डी में 159 और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 273 उम्मीदवारों को कुल 530 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे दिवंगत अधिकारियों के परिवारों को भी राहत मिली।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्यगान से हुई। इसे सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात लगे रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पुलिस अधीक्षक डॉ. डी. स्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिश्चंद्र पाटिल और अन्य अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम योगदान दिया। जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों को याद दिलाया कि यह नियुक्ति सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि राज्य और जनता की सेवा का अवसर है। उन्होंने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारी ही समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारी और कार्यकर्ता इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता में शामिल रहे और नवनियुक्त कर्मचारियों के भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस कार्यक्रम ने यह भी दिखाया कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से योग्य और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में कितनी सक्रिय है। आगामी समय में यह नियुक्ति महाराष्ट्र प्रशासन में नयी ऊर्जा और दक्षता लाने का अवसर साबित होगी।

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट, दो बच्चों की मौत, आठ गंभीर घायल

(जीएनएस)। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले के कादरी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को सातनपुर मंडी के पास संचालित एक कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे करीब दस बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि एक किलोमीटर दूर तक कई मकान हिल गए।

विस्फोट से कोचिंग सेंटर का पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। अंदर की स्लैब और पक्की दीवारें बाहर उछल कर 50 मीटर दूर तक जा गिरीं, वहीं लोहे की जाली डेढ़ सौ मीटर दूर पानी के गड्ढे में फेंक दी गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ छात्रों के शरीर के मांस के लोथड़े घटना स्थल पर ही पड़े मिले।

विस्फोट की वजह से आसपास खड़ी मोटरसाइकिल, स्कूटी और साइकिल जैसे वाहन भी 50 मीटर दूर तक उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फतेहगढ़ व कादरी गेट थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल भी घटना स्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई।

पुलिस ने कोचिंग सेंटर में मौजूद एक शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि विस्फोट किसी विस्फोटक या रासायनिक पदार्थ के कारण हुआ हो सकता है, लेकिन सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। घायल बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और प्रशासन ने परिवारों को घटनास्थल पर आने से रोकते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला दी है। फर्रुखाबाद के लोगों में इस हादसे को लेकर गहरा शोक और भय व्याप्त है। प्रशासन ने सभी स्कूल और कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी है। इस भयानक हादसे ने क्षेत्र के निवासियों को झकझोर कर रख दिया है और पूरे जिले में सुरक्षा के मानकों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर कर दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान- 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' का गांधीनगर में शुभारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण :-

- इस अभियान के जरिए नागरिकों द्वारा बचाए गए प्रत्येक रुपए को उन्हें या उनके परिवार को वापस किया जाएगा
- केवाईसी और री-केवाईसी अभियान में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, विशेषकर गुजरात ग्रामीण बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका

गुजरात से शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा : श्री कनुभाई देसाई, वित्त मंत्री, गुजरात

केंद्रीय वित्त मंत्री सहित महानुभावों के करकमलों द्वारा लाभार्थियों को उनके रुपए वापस किए गए

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में शनिवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर गांधीनगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अभियान की सफलता के लिए शुभकामना संदेश प्रेषित किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अभियान एक सरल, लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है कि नागरिकों द्वारा बचाया गया प्रत्येक रुपया उन्हें या उनके परिवार को वापस करना चाहिए। बिना दावे वाली बैंक जमा राशि (डिपॉजिट्स), बीमा पॉलिसी की आय, लाभांश, म्यूचुअल फंड आय और पेंशन केवल कागज पर दर्ज एंट्रियां नहीं है, बल्कि वह सामान्य परिवारों की मेहनत से कमाई हुई बहुमूल्य पूंजी-बचत है। यह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाएगी।

उन्होंने कहा कि 31 अगस्त, 2025 तक विभिन्न बैंकों ने लगभग 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हस्तांतरित की है। इसके अलावा, आरबीआई के पास बीमा क्षेत्र में लगभग 14 हजार करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में 3 हजार करोड़ रुपए, कंपनियों में 9 हजार करोड़ रुपए और 19 हजार करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बिना दावे के पड़े हैं। इस प्रकार, देश में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं, यदि यह राशि वापस लौटाई जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में तीन 'ए' – जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। जागरूकता का उद्देश्य नागरिक और समुदाय को बिना दावे वाली संपत्तियों का पता लगाने के तरीके के बारे में सूचित करना है। जबकि पहुंच का उद्देश्य सरल डिजिटल उपकरणों और जिला स्तरीय पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं, कार्रवाई का उद्देश्य समयबद्ध और पारदर्शी दावे के निपटान पर जोर देना है। ये तीनों स्तंभ साथ मिलकर नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेंगे, समुदाय जागरूकता को बढ़ावा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और आसानी के साथ अपनी सही बचत वापस प्राप्त कर सके।

वित्त मंत्री ने हाल ही के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और री-केवाईसी (पुनः केवाईसी) अभियान में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, विशेषकर गुजरात ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने नागरिकों और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के बीच के जुड़ाव को मजबूत बनाया है। गांवों और नगरों में शुरू किए गए इन प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभार्थी अपनी बचत और अधिकार के साथ जुड़े रहते हैं, जो वर्तमान अभियान की सफलता के लिए एक मजबूत आधार साबित होगा। वित्त मंत्री ने सभी संस्थानों से अनुरोध किया कि वे इस राष्ट्रव्यापी पहल के दौरान दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों को लेकर समान समर्पण दिखाएं और पहुंच बढ़ाएं ताकि कोई भी नागरिक अपने हक के पैसे से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि यह अभियान जन धन योजना और यूपीआई से लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तक, वित्तीय समावेश में भारत की व्यापक उपलब्धियों पर आधारित है ताकि नागरिक न केवल वित्तीय सेवाएं ही नहीं, बल्कि जिसके हकदार हैं, उसे भी वापस प्राप्त कर सकें। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक यानी तीन महीनों के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। डिजिटल प्रदर्शनी और हेल्प डेस्क नागरिकों को उनकी बिना दावे की वित्तीय संपत्तियों का आसानी से पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करेंगे, जो नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और जीवन को आसान बनाने के उनके व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान- 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा। इस अभियान के जरिए बैंक के बचत खाते में, बीमा कंपनियों में, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसे क्षेत्रों में वर्षों से बिना दावे के पड़े उनके रुपए उन्हें सम्मान के साथ वापस मिल रहे हैं। यह रुपए उनके परिवार में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोगी होंगे, जिसके चलते ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 2500 करोड़ रुपए तथा बीमा कंपनियों में लगभग 235 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि पड़ी है, जो इस अभियान के माध्यम से उनके असली मालिकों को वापस की जाएगी। गुजरात सरकार के सभी विभागों में इस प्रकार की रकम के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर संबंधित लोगों के घर तक उनके अधिकार की राशि पहुंचाई जाएगी। श्री देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को विश्वास दिलाया था कि जीएसटी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी, जिसका केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के सक्रिय प्रयासों से नवरात्रि के पहले दिन से देश भर में क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री के मंत्र 'ईज ऑफ लिविंग' को बल मिला है। इतना ही नहीं, आम नागरिकों को भी इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। गुजरात में पिछले 10 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष नए वाहनों की बिक्री 10 गुना अधिक हुई है। उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए गुजरात का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का गुजरात सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया।

वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे की संपत्तियों के कुशल और त्वरित समाधान की सुविधा के लिए इस अभियान में उपस्थित महानुभावों ने विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी स्टॉलों का दौरा कर जानकारी हासिल की।

केंद्रीय वित्त मंत्री सहित महानुभावों के करकमलों द्वारा म्यूचुएल फंड, कॉर्पोरेट फंड, बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अभियान की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का विमोचन किया। समारोह में केंद्रीय वित्त विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत गुजरात से की जा रही है। आज केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जन धन योजना, यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके भाग के रूप में, वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लेकर बैंकिंग और शासन में सुधारों के साथ-साथ देश में समावेशी वित्तीय व्यवस्था की एक मजबूत नींव रखी गई है।

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री आशीष मोरे ने स्वागत भाषण में कहा कि गुजरात से शुरू हुआ यह राष्ट्रीय अभियान सरकार, संस्थानों और नागरिकों को जोड़ने वाला अभियान है। इसके जरिए नागरिकों की मेहनत की कमाई की बचत और पूंजी का प्रत्येक भाग उन्हें या उनके परिवार तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के अंतर्गत बैंक में जमा राशि, बीमा दावे, म्यूचुअल फंड, लाभांश और पेंशन के रूप में जो बड़ी धनराशि बिना दावे के पड़ी है, उसे नागरिकों तक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस अभियान को केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि जनजागरूकता अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद जोन के महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) गुजरात के संयोजक श्री अश्विनी कुमार ने आभार व्यक्त किया।

समारोह में राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. टी. नटराजन, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती आरती कंवर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विक्रांत पांडे, केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), संबंधित बैंक और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थानों जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित कई लाभार्थी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा समन्वित यह अभियान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) बैंक और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थानों के साथ एक सामान्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

6 से 9 अक्टूबर तक गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महेसाणा-गोझरिया हाईवे के बीच गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 आंबलियासन-विजापुर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत चेक रेल एवं रोड अलाइनमेंट पर डामर कार्य के चलते 6 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर 2025 तक (4 दिन) बंद रहेगा।

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान गांधीनगर-गोझरिया-विसनगर हाईवे स्थित रेलवे फाटक नं. 77 से आवागमन

25,000 से $21 बिलियन साम्राज्य तक: वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में टॉरेंट ग्रुप संस्थापक स्व. श्री यू.एन. मेहता की प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव

- **स्व. श्री यू.एन. मेहता: भारत में फार्मा और पावर सेक्टर के अग्रणी, जिन्होंने बनाया एक कॉर्पोरेट दिग्गज और एक अमूल्य उदारवादी विरासत**
- **वीजीआरसी नॉर्थ गुजरात में सम्मान: स्व. श्री यू.एन. मेहता जैसे दूरदर्शी उद्यमियों को सलाम, जिन्होंने बदल दी भारत की उद्योग और विकास की कहानी**

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात की पवित्र धरती ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत की प्रगति की दिशा तय की। इन्हीं में से एक हैं श्री उत्तमभाई नथालाल मेहता (14 जनवरी, 1924 – 31 मार्च, 1998) जो टोरेंट ग्रुप के संस्थापक और भारतीय उद्योग जगत के उज्ज्वल चमकता सितारा हैं। उन्होंने उस समय दवाओं का उत्पादन शुरू किया, जब भारत जीवनरक्षक दवाओं के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था। केवल यही नहीं, बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भी उन्होंने वैश्विक मानकों वाली परियोजनाएँ खड़ी कीं और भारत को गहरे बिजली संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। श्री मेहता का जीवन गुजरात की उस उद्यमशीलता का प्रतीक है, जिसने न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह दिखाई।

एक सामान्य युवक से उद्योग जगत में चमकता सितारा बनने की कहानी

उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के छोटे से गाँव मेमदपुर में जन्मे श्री यू.एन. मेहता का जीवन इसी भावना का जीवंत उदाहरण है। अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे और मात्र दो वर्ष की आयु में माता का साया खो देने वाले इस बालक ने कभी हार नहीं मानी। संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया। वहाँ विल्सन कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की जो उनकी आगे की औद्योगिक यात्रा के लिए मजबूत नींव साबित हुई।

परिस्थितियाँ कठिन थीं, लेकिन हौसले भी बुलंद थे। आर्थिक अभावों के चलते उच्च शिक्षा का उनका सपना अधूरा रह गया, फिर भी उन्होंने 1944 में सरकारी नौकरी कर अपने जीवन की नई शुरुआत की। जल्द ही उन्होंने 1945 से 1958 तक स्विस फार्मा कंपनी 'सैंडोज़' में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। यहीं से उन्होंने औषधि उद्योग की बारीकियाँ सीखीं और एक दिन अपना कुछ करने का स्वप्न देखा।

साहस, संकल्प और दूरदर्शिता से उद्योग जगत में हुए प्रसिद्ध श्री यू.एन. मेहता

1959 में श्री यू.एन. मेहता ने साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मात्र 25,000 रुपये की पूँजी से अहमदाबाद में 'ट्रिनिटी लेबोरेट्रीज़' (अब टोरेंट फार्मा) की स्थापना की। यह उस दौर की बात है जब भारत विदेशी दवाओं पर निर्भर था और देश में फार्मा उत्पादन की कल्पना भी कठिन मानी जाती थी। लेकिन गुजरात की धरती पर जन्मे इस कर्मयोगी ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया।

जीवन ने उन्हें बार-बार परखा। 39 वर्ष की आयु में दवा के दुष्प्रभाव से मानसिक बीमारी, 53 वर्ष में दुर्लभ प्रकार का कैंसर, और 62 वर्ष में हृदय रोग के कारण बाईपास सर्जरी जैसी गंभीर परिस्थितियाँ सामने आईं। उनका पहला व्यावसायिक प्रयास भी असफल रहा, और उन्हें अपने गाँव लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ वे फिर उठ खड़े हुए। 48 वर्ष की आयु में वो पुनः सफलता के शिखर तक पहुँच गए और गुजरात को दिया एक ऐसा औद्योगिक अग्रणी जिसने देश को आत्मनिर्भर औषधि निर्माण की दिशा दिखाई।

दूरदर्शिता से शुरू हुई टोरेंट समूह की सफलता की यात्रा

1968 में जब भारत का औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में था, तब श्री यू.एन. मेहता ने अपनी असाधारण दूरदृष्टि और साहस के साथ मनोचिकित्सा संबंधी दवाओं के निर्माण और विपणन की पहल की। यह कदम उस दौर में किसी भी भारतीय उद्यमी के लिए जोखिमपूर्ण था, परंतु श्री मेहता ने इसे देश की आवश्यकता और आत्मनिर्भरता के संकल्प के रूप में अपनाया। उनकी यही नवोन्मेषी सोच और "नीश मार्केटिंग" रणनीति टोरेंट समूह की सशक्त नींव बनी, जिसने आगे चलकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और खेल जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया। आज टोरेंट समूह का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2025 तक 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच चुका है। टोरेंट समूह आज गुजरात की उस नवाचार-प्रधान औद्योगिक संस्कृति का प्रतीक है, जो परिश्रम, दृष्टि और सामाजिक उत्तरदायित्व को साथ लेकर चलती है।

सेवा को समर्पित जीवन, संस्कारों से संवरती विरासत

श्री मेहता केवल एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि संवेदनशील समाजसेवी भी थे। उन्होंने जनस्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर (UNMICRC) की स्थापना की, जो आज भी वंचित वर्गों को सस्ती और सुलभ हृदय चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। उनकी पत्नी, श्रीमती शारदाबेन मेहता ने भी बाल स्वास्थ्य और कन्या शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए समाजसेवा को नई दिशा दी और UNMICRC की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

उनकी चारों संताने सुधीर, समीर, मीना और नयना आज भी अपने माता-पिता के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए, टोरेंट समूह को नई ऊँचाइयों तक ले जा रही हैं और समाजहित के कार्यों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी जन्मशताब्दी (2024) के अवसर पर मेहता परिवार ने यू.एन.एम. फाउंडेशन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान-विस्तार, पर्यावरण, कला-संस्कृति और सामाजिक कल्याण हेतु दान करने की भी घोषणा की।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस बनेगा स्थानीय नेतृत्व, साझा दृष्टि और सतत प्रगति का संगम

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से गुजरात सरकार यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि विकास केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साझा दृष्टि, ठोस योजना और सतत प्रयास का परिणाम है। इस पहल के जरिये सरकार यह प्रतिपादित कर रही है कि राज्य के हर कोने में प्रगति को सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व, नीति और सामूहिक भागीदारी का होना अनिवार्य है। श्री यू.एन. मेहता जैसे दूरदर्शी औद्योगिक नेतृत्व इस दृष्टि के जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम और स्पष्ट दिशा के साथ न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित किया, बल्कि समावेशी और सतत विकास की नई राह भी दिखाई।

पटेल ने 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' विक्रम संवत-2081 का विमोचन किया

27 शोध लेखों, 31 लघु उपन्यासों, 17 व्यंग्य रचनाओं, 11 नाटिकाओं, 97 काव्य रचनाओं एवं मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती 51 रंगीन तस्वीरों एवं मनमोहक चित्रों से सजा दीपोत्सवी अंक

(जीएनएस)। गांधीनगर, : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' विक्रम संवत 2081 का विमोचन किया। राज्य के सूचना विभाग की ओर से प्रति वर्ष प्रकाशित किए जाने वाले दीपोत्सवी अंक की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' के माध्यम से गुजरात के साहित्य, कला, इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और संस्कार विरासत को प्रस्तुत किया गया है।

दीपोत्सवी अंक के विमोचन अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव और सूचना एवं प्रसारण विभाग की सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सूचना निदेशक श्री के.एल. बचाणी, अपर सूचना निदेशक श्री अरविंदभाई पटेल सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

इस वर्ष दीपोत्सवी-2081 में गुजरात के मूर्धन्य साहित्यकारों की रचनात्मक कलम के माध्यम से ऐसे चिंतनात्मक विचारों, काव्यों, लघु उपन्यासों, व्यंग्य रचनाओं और नाटिकाओं युक्त भव्य और विविध साहित्य परोसा गया है, जिसकी खूशबू से पाठक मित्रों का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इतना ही नहीं, गुजरात के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों की सृजनशील कलम द्वारा लिखी गई साहित्यिक कृतियां दीपोत्सवी अंक में प्रकाशित की गई हैं। यह शानदार अंक 27 शोध लेखों, 31 लघु उपन्यासों, 17 व्यंग्य रचनाओं, 11 नाटिकाओं और 97 काव्य रचनाओं से संपन्न है। इसके साथ ही, प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती करीब 51 रंगीन तस्वीरें और मनमोहक चित्र इस अंक को और भी नयनरम्य बनाते हैं।

5 और 6 अक्टूबर को चलेगी साबरमती–गुड़गाँव और मुंबई–सेंट्रल–साबरमती वंदे भारत वन वे स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से साबरमती-गुड़गाँव और मुंबई सेंट्रल-साबरमती के बीच विशेष किराये पर वंदे भारत सुपरफास्ट वन वे स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09401 साबरमती–गुडगाँव वंदेभारत सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09401 साबरमती-गुडगाँव वंदेभारत स्पेशल 5 और 6 अक्टूबर 2025 को साबरमती से 17.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08.25 बजे गुडगाँव पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी के कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल–साबरमती वंदेभारत सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल-साबरमती वंदेभारत स्पेशल 5 और 6 अक्टूबर 2025 को मुंबई सेंट्रल से 10.30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 17.20 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09401 और 09153 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हैं। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ब्लॉक के कारण 8 और 9 अक्टूबर की पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित

(जीएनएस)। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में कोलाघाट स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य हेतु 02 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न चरणों में NI कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 13 अक्टूबर, 2025 को 4 घंटे का पूर्ण ब्लॉक लेकर कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल से संचालित पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन (12905) प्रभावित होगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. 8 अक्टूबर, 2025 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 75 मिनट देरी से चलेगी।
2. 9 अक्टूबर, 2025 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेनों के समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

नांदगांव स्टेशन पर बड़े रीमॉडलिंग कार्य की शुरुआत, यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ेगा असर

(जीएनएस)। भुसावल मंडल का नांदगांव स्टेशन आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव से गुज़रने वाला है। जलगांव – मनमाड खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के साथ-साथ लंबी हॉल लूप लाइन निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में यहाँ यार्ड रीमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। रेलवे ने इस कार्य के लिए विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लागू किया है, जिससे तीन दिनों तक ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर पड़ेगा। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या और मालगाड़ियों के दबाव को देखते हुए रेल यातायात को और अधिक सुरक्षित, सुगम और तेज़ बनाना है। नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था पुरानी मैन्युअल प्रणाली की जगह लेगी, जिससे ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित नियंत्रण में आ सकेगा।

लेकिन इसके चलते 7 और 8 अक्टूबर 2025 को कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी। इनमें देवळाली – भुसावल एक्सप्रेस (11113), भुसावल – देवळाली एक्सप्रेस (11114), इगतपुरी – भुसावल मेमू (11119) और भुसावल – इगतपुरी मेमू (11120) शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को अग्रिम चेतावनी देते हुए अपनी यात्रा योजनाएँ बदलने और वैकल्पिक गाड़ियों का विकल्प तलाशने की सलाह दी है।

इतना ही नहीं, 9 अक्टूबर 2025 को भी वही चारों ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई लंबी दूरी की गाड़ियाँ विलंब से चलेंगी। इनमें लोकमान्य टिळक टर्मिनस – हरिद्वार एक्सप्रेस (12171) लगभग 2 घंटे 30 मिनट देरी से, लोकमान्य टिळक टर्मिनस – गोड्डा एक्सप्रेस (22312) 2 घंटे देरी से और मुंबई – लखनऊ एक्सप्रेस (12534) 2 घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचेंगी।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह असुविधा केवल अस्थायी है और कार्य पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु और सुरक्षित हो जाएगी। नांदगांव स्टेशन को एक आधुनिक स्वरूप देने की इस परियोजना से क्षेत्रीय यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

यानी फिलहाल यात्रियों को थोड़ी परेशानी ज़रूर झेलनी होगी, लेकिन आने वाले समय में यही असुविधा रेलवे की सुविधा और विश्वसनीयता में बदल जाएगी।

लातेहार में अफीम पर सख्त वार: पुलिस ने शुरू किया जागरूकता और दमन अभियान, सूचना छिपाने वालों पर भी कार्रवाई होगी

(जीएनएस)। लातेहार ज़िले में अफीम की अवैध खेती को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने इस बार पहले से कहीं अधिक कठोर रुख अपनाया है। पिछले वर्ष लगभग 800 एकड़ भूमि पर फैली अफीम की खेती को नष्ट करने के बाद इस बार लक्ष्य रखा गया है कि जिले की एक इंच जमीन पर भी यह ज़हरीली फसल न उगे। इसके लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी किसान लालच या डर में आकर इस अवैध कार्य में शामिल न हो।

पुलिस की टीमें अब गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रही हैं। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अफीम की खेती न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह उनकी ज़मीन, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बर्बाद करती है। पुलिस अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं कि अफीम से मिलने वाला धन क्षणिक है, लेकिन उसके परिणाम आजीवन विनाशकारी हैं। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में यह खेती की, उनके खेत अब बंजर हो चुके हैं और उन पर कानूनी मुकदमे चल रहे हैं।

अभियान के तहत ग्राम प्रधानों, मुखियाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, वनकर्मियों और चौकीदारों को भी चेताया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में अफीम की खेती की सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी कुमार गौरव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, "यह सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ अभियान है जो किसी भी रूप में अफीम की खेती को बढ़ावा देता है या उसकी जानकारी छिपाता है।"

लातेहार के हेरहंज, बालूमाथ, बारियातू और चंदवा जैसे इलाकों को लंबे समय से अफीम की खेती के लिए कुख्यात माना जाता रहा है। यहाँ बाहरी तस्कर अक्सर ग्रामीणों को नकदी के लालच में फँसाकर सरकारी और वनभूमि पर खेती करवा लेते हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच जब यह खेती शुरू होती है, तो पूरी प्रक्रिया गुप्त रूप से रात के अंधेरे में की जाती है। इसके बाद अफीम को छोटे-छोटे नेटवर्कों के माध्यम से बाहर के राज्यों और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। हर गाँव में लोगों से शपथ दिलाई जा रही है कि वे अपने खेतों में कभी अफीम की खेती नहीं करेंगे और यदि किसी को ऐसा करते देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचना देंगे।

ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि अफीम की खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और धीरे-धीरे वह ज़मीन खेती योग्य नहीं रहती। इससे न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है, बल्कि गाँवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना भी टूट जाती है। कानून के अनुसार, अफीम की खेती में पकड़े जाने पर दोषी को 20 साल तक की कठोर सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। इसी के साथ प्रशासन अब वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। किसानों को सब्जियों, दालों और फलदार वृक्षों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एसपी कुमार गौरव ने कहा कि ऐसे किसानों को हरसंभव सहायता दी जाएगी ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उन्हें अफीम जैसी अवैध फसल की ओर लौटने की कोई जरूरत न पड़े। "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई किसान आर्थिक मजबूरी में अपराध की राह न पकड़े," उन्होंने कहा। पिछले साल चले अभियान से तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा था। पुलिस ने 800 एकड़ से अधिक भूमि पर उगी अफीम की फसल नष्ट की थी और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस बार भी अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा। जिला पुलिस ने साफ कर दिया है कि चाहे खेती करने वाला हो या सूचना छिपाने वाला — किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

लातेहार प्रशासन की इस पहल ने एक स्पष्ट संदेश दिया है: राज्य अब नशे की इस जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज को बचाने का संघर्ष है — ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य अफीम के अंधकार में नहीं, कृषि की हरियाली में खिले।

पाकिस्तान से लगातार विदा ले रहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गहराया संकट

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) पर गहरा असर डाल रहे हैं। अमेरिकी दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने हाल ही में पाकिस्तान में अपना उत्पादन रोकने का ऐलान किया, जबकि इसकी सहायक कंपनी जिलेट ने भी कारोबार समेट लिया है। कभी शेविंग से जुड़े उत्पादों के लिए मशहूर जिलेट का राजस्व दो साल में घटकर केवल तीन अरब पाकिस्तानी रुपये रह गया। इससे पहले उबर, एलि लिली, यामाहा मोटर्स जैसी 10 से अधिक कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं।

पीएंडजी पाकिस्तान में बच्चों के डायपर और अन्य बुनियादी उपभोक्ता उत्पाद बनाती थी, जबकि जिलेट रेजर, क्रीम, फोम और ब्लेड तैयार करती थी। इनके बंद होने से अब आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है।

पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल (पीबीसी) के पूर्व सीईओ एहसान मलिक का कहना है कि कंपनियों को कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी नहीं मिली और बौद्धिक संपदा

अधिकारों का पालन भी सही तरीके से नहीं हो रहा था। यही कारण है कि कई कंपनियों ने पाकिस्तान छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कुछ कंपनियां अपनी वैश्विक रणनीतियों के चलते भी जा रही हैं।

दूसरी तरफ, पाकिस्तान में पहले से ही ब्रेन ड्रेन की समस्या गहराती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और अकाउंटेंट विदेश पलायन कर चुके हैं। हाल ही के एक सर्वे में 40% युवाओं ने माना कि वे पाकिस्तान छोड़कर बाहर काम करना चाहते हैं। पीएंडजी के उत्पादन बंद करने से भी हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। युवा वर्ग खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। औसतन 50 हजार से दो लाख रुपये कमाने वाले युवाओं के लिए जीवन-यापन मुश्किल हो गया है। भारत और बांग्लादेश की तुलना में पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान में जरूरी वस्तुओं की कीमतें तीन से चार गुना बढ़ चुकी हैं। सरकार भी अब विदेशी रेमिटेंस पर निर्भर होती जा रही है। विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तानी हर साल लगभग 30 अरब डॉलर भेजते हैं, जिससे कई परिवारों का जीवन चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, एमएनसी देश के राजस्व में लगभग 20% और रोजगार में 5% से अधिक का योगदान देती थीं।

पिछले दो वर्षों में कई दिग्गज कंपनियां पाकिस्तान को अलविदा कह चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद जुलाई 2024 में काम बंद किया। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने मई 2024 में कराची स्थित अपना प्लांट बेच दिया। शेल ग्लोबल ने नवंबर 2023 में शेल पाकिस्तान लिमिटेड से पूरी हिस्सेदारी बेची। फ्रांस की टोटल एनर्जी और नॉर्वे की टेलीनॉर भी क्रमशः 2024 और 2022 में पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं।

भाजपा ने गुजरात में बदला सियासी संतुलन: ओबीसी नेता जगदीश विश्वकर्मा बने नए प्रदेश अध्यक्ष, शाह-मोदी की जोड़ी ने चलाया रणनीतिक दांव

(जीएनएस)। गुजरात की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। लंबे समय से इस पद पर बने सी.आर. पाटिल की जगह अब राज्य मंत्री और अमित शाह के विश्वस्त माने जाने वाले 52 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात भाजपा की कमान सौंपी गई है। यह निर्णय न केवल भाजपा के भीतर नई ऊर्जा का संकेत देता है, बल्कि प्रदेश की जातीय और राजनीतिक गणित में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इशारा करता है।

जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद शहर से आने वाले पहले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और साथ ही ओबीसी समुदाय से आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने सुबह अहमदाबाद के कैंप हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर दिन की शुरुआत की और फिर गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय 'कमलम' पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों, पारंपरिक नृत्य और पुष्पवर्षा के बीच माहौल उत्सव जैसा था।

मुख्यालय में आधिकारिक घोषणा के बाद जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो पूरा परिसर 'भारत माता की जय' और 'जगदीशभाई विश्वकर्मा ज़िंदाबाद' के नारों से गूंज उठा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी और संगठन के विस्तार की नई दिशा पर चर्चा की। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "जगदीश विश्वकर्मा हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझते हैं और समाधान निकालते हैं। यही कारण है कि आज उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।"

इस नियुक्ति के पीछे भाजपा की रणनीतिक सोच स्पष्ट झलकती है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद से पार्टी को लगातार संतुलन साधने की चुनौती रही है। पाटीदार, क्षत्रिय, अहीर, ठाकोर और कोली जैसे प्रभावशाली वर्गों के साथ-साथ ओबीसी समुदायों में भी भाजपा की पकड़ बनाए रखना संगठन की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए था, जो न केवल ओबीसी समाज से हो बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकार्य भी हो।

पिछले कुछ हफ्तों से इस पद को लेकर भीतरखाने में कई नाम चल रहे थे। पाटीदार और ठाकोर नेताओं के बीच खींचतान के साथ-साथ कुछ कांग्रेस से आए नेताओं ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। परंतु अंततः भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व — खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह — ने जगदीश विश्वकर्मा पर भरोसा जताया। दोनों का मानना है कि विश्वकर्मा संगठन में संतुलन बनाए रखते हुए आने वाले चुनावों के लिए मजबूत रणनीतिक ढांचा तैयार कर सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि चुनावी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2026 में होने वाले निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा अब नई सामाजिक बुनावट तैयार कर रही है। ओबीसी वर्ग राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है और विश्वकर्मा की नियुक्ति से पार्टी ने इस समुदाय को यह संदेश दिया है कि उनकी भागीदारी संगठन में सर्वोच्च स्तर पर सुनिश्चित है।

अहमदाबाद के उद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय और तकनीकी पृष्ठभूमि से आने वाले जगदीश विश्वकर्मा अपने शांत स्वभाव और निर्णायक प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उद्योग, कौशल विकास और श्रम विभाग में मंत्री के रूप में काम करते हुए कई नवाचार किए हैं। उनका दृष्टिकोण विकास और सामाजिक सामंजस्य दोनों पर आधारित है, जो भाजपा की वर्तमान वैचारिक दिशा से मेल खाता है।

पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा, "भाजपा के लिए काम करना मेरे लिए एक सेवा है, सत्ता नहीं। मेरा लक्ष्य है कि हर कार्यकर्ता अपने आप में संगठन का स्तंभ बने। आने वाले वर्षों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गुजरात को विकास के नए शिखर पर पहुँचाएंगे।"

महामंडलेश्वर पद से हटाई गईं पूजा शकुन भारती, निरंजनी अखाड़े से भी निष्कासित — गांधी के पुतले को गोली मारने से लेकर हत्या साजिश के आरोप तक

(जीएनएस)। अलीगढ़ की विवादित संत और स्वघोषित साध्वी पूजा शकुन भारती को निरंजनी अखाड़े और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दोनों से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही उनका महामंडलेश्वर पद भी समाप्त कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पूरी जी महाराज ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि पूजा शकुन के कार्य और आचरण ने न केवल अखाड़े की गरिमा को ठेस पहुँचाई है, बल्कि सनातन परंपरा की मर्यादाओं के विरुद्ध भी व्यवहार किया है।

रविंद्र पूरी जी महाराज ने बताया कि जब पूजा शकुन को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब उनके धार्मिक कार्यों और योग्यता को देखते हुए उन्हें यह पद दिया गया था। अखाड़े को उम्मीद थी कि वह समाजसेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान देंगी। लेकिन हाल के घटनाक्रमों और उनके विवादित बयानों ने संगठन की छवि को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा, "अखाड़ा परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूजा शकुन को निरंजनी अखाड़े की सदस्यता और महामंडलेश्वर पद से निष्कासित किया जाए। उनके कृत्य अब किसी भी रूप में क्षम्य नहीं हैं।"

पूजा शकुन पहले भी विवादों में रही हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाई थी और उस समय उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी। हालांकि, उस समय राजनीतिक कारणों से इस पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई, पर अब अखाड़ा परिषद का कहना है कि उनका बार-बार विवादों में आना धार्मिक संस्थाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक है। इस बीच अलीगढ़ पुलिस ने पूजा शकुन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने उनके विरुद्ध अदालत से एनवीडब्ल्यू (नॉन-बेलेबल वारंट) जारी करवाया है। यदि वे जल्द सामने नहीं आईं या गिरफ्तार नहीं की गईं, तो पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करेगी। गौरतलब है कि पूजा शकुन वर्तमान में अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में साजिश की आरोपी हैं। जिला पुलिस ने उनके नाम पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार, वह हत्या की साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थीं और फिलहाल फरार हैं। अखाड़ा परिषद का यह निर्णय संत समाज के भीतर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है कि धार्मिक संस्थाएं अब ऐसे विवादास्पद चेहरों से दूरी बनाने के मूड में हैं, जो आध्यात्मिक मूल्यों के बजाय राजनीति और हिंसा के रास्ते पर चलकर संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पूजा शकुन आगे क्या कदम उठाती हैं — आत्मसमर्पण करती हैं या फरारी जारी रखती हैं। लेकिन इतना तय है कि उनके खिलाफ धार्मिक और कानूनी, दोनों मोर्चों पर हालात बेहद कठिन हो चुके हैं।

यूपी में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का कहर, 96 घंटे बंपर बारिश का अलर्ट

(जीएनएस)। लखनऊ। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान 'शक्ति' के कारण शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। कई जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर नदी जैसी स्थिति बन गई। बनारस, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहे। बनारस के कई इलाकों में घरों, दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मऊ और जौनपुर में भी यही आदेश लागू किया गया है।

मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को भी पूर्वी यूपी के इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसतन 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य बारिश मात्र 1.5 मिमी होती है। यानी यह सामान्य से लगभग 367 प्रतिशत ज्यादा है। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 82 प्रतिशत कम है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि अगले 96 घंटे यानी चार दिन तक बारिश का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर में बिजली गिरने और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इन 18 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बलिया, गाजीपुर, मऊ और देवरिया जिलों के कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले छह घंटों तक इन जिलों में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहेगी, जबकि बलिया में अगले 24 घंटे तक स्थिति गंभीर रह सकती है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बनारस ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीएचयू वेदर स्टेशन के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 5 बजे तक बनारस में 184.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले साल 1900 में यहां 138.2 मिमी बारिश हुई थी। यह नया रिकॉर्ड न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी है कि 'शक्ति' नाम का यह चक्रवाती तूफान फिलहाल थमने वाला नहीं। बनारस के घाटों पर भी बारिश का असर दिखा। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जबकि घाटों के आसपास के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की दो टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश अभी तीन दिन और जारी रह सकती है, जिसके चलते किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिजली विभाग ने बारिश और तूफान के कारण बार-बार ट्रिप हो रही लाइनों को लेकर विशेष निगरानी टीम बनाई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संभावित जलजनित रोगों को रोकने के लिए जिलों में मेडिकल टीमों की तैनाती शुरू कर दी है।

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय जो हालात हैं, वे यह संकेत देते हैं कि 'शक्ति' तूफान का असर न केवल मानसून की सक्रियता को बढ़ा रहा है, बल्कि यह उत्तर भारत के मौसमीय संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति सुधरने की उम्मीद कम है, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता और राहत प्रयासों से नुकसान को कम किया जा सकता है।

दिल्ली में यमुना घाटों पर भव्य छठ महापर्व का आयोजन सुनिश्चित, CM रेखा गुप्ता ने तैयारियों का लिया जायजा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को यमुना नदी के घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने नदी पर नाव की सवारी करके भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार छठ का आयोजन भव्य और सुचारू रूप से किया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सनातनी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के घाटों पर छठ महापर्व का आयोजन ऐतिहासिक और सुरक्षित रूप से हो।

मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को 25 से 28 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले चार दिवसीय छठ महापर्व की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में बताया कि पिछली सरकार की लापरवाही के कारण कई वर्षों तक यमुना किनारे छठ पर्व आयोजित नहीं हो सका। पूर्वांचली समुदाय के लोग अपने पारंपरिक उत्सव से वंचित रहे।

रेखा गुप्ता ने कहा, "अब एक सनातनी सरकार है और यह हमारा कर्तव्य है कि दिल्ली में छठ महापर्व का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। हमने तय किया है कि छठ पर्व यमुना किनारे मनाया जाएगा। हमने आईटीओ से वजीराबाद तक यमुना किनारे अस्थायी घाटों के लिए हर बिंदु का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि लोग सुविधा के साथ पर्व मना सकें।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतों ने यमुना जल में विसर्जन की अनुमति नहीं दी है, इसलिए विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत यमुना मैया के आशीर्वाद से हुई। उन्होंने बताया कि यह पहला अवसर है जब चुनाव के बाद यमुना किनारे छठ पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी यह ऐतिहासिक निर्णय लिया और इसे सफल बनाने में प्रशासन को मार्गदर्शन दिया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना नदी और अन्य क्षेत्रों में अस्थायी घाट बनाने के लिए कम से कम 100 स्थानों की पहचान की है। इन सभी जगहों पर सुरक्षा, साफ-सफाई, बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि इस बार छठ महापर्व का आयोजन नियमों और सुरक्षा निर्देशों के पालन के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सभी नागरिकों को पर्व मनाने की उत्तम सुविधाएं प्रदान करेगी और इस ऐतिहासिक आयोजन को सभी के लिए यादगार बनाएगी।

इस तरह, दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ महापर्व का भव्य आयोजन निश्चित होने से पर्व का ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर दोनों संरक्षित रहेंगे, और राजधानी में पहले से बाधित परंपरा को पुनः जीवित किया जाएगा।

पति को उतारा मौत के घाट,पहले सिल बट्टे से किया अधमरा फिर चाकू से गला रेता

(जीएनएस)। वाराणसी। लल्लापुरा इलाके में शुक्रवार को मदरसा शिक्षक दानिश की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। शनिवार को पुलिस ने इस रहस्यमयी हत्या का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि दानिश की हत्या उसकी पत्नी रुबीना ने ही की। पुलिस पूछताछ में रुबीना ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पति की रोज़मर्रा की प्रताड़ना ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने मौत का रास्ता चुन लिया।

40 वर्षीय दानिश एक मदरसे में सरकारी शिक्षक थे। पढ़ा-लिखा परिवार होने के बावजूद घर की आर्थिक हालत खराब थी। लेकिन असली समस्या दानिश की आदतें थीं। पत्नी रुबीना के अनुसार, दानिश रोज़ शराब पीकर घर लौटता और किसी न किसी बात पर उसे बेरहमी से पीटता था। घर के अन्य सदस्य भी उसके समर्थन में रहते, जिससे रुबीना को न्याय और सहारा कहीं से नहीं मिलता। रुबीना ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की रात भी दानिश ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा। यहां तक कि बेटा भी मजाक उड़ाता था और धमकाता था कि अगर कुछ कहोगी तो पापा से कह दूंगा और वह तुम्हें और मारेंगे। इस माहौल ने रुबीना का धैर्य पूरी तरह तोड़ दिया। उसी रात उसने अपने पति की हत्या का फैसला कर लिया।

पुलिस पूछताछ में रुबीना ने कबूल किया कि जब दानिश गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने पहले सिल के बट्टे से उसके सिर पर लगातार कई वार किए। जब वह अधमरा हो गया, तो रुबीना ने घर में रखा चाकू उठाया और उसका गला रेत दिया। इसके बाद भी उसने चाकू से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए ताकि वह बिल्कुल भी जिंदा न बचे।

एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि देर रात तक चली पूछताछ में रुबीना ने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सिल का बट्टा और चाकू बरामद कर लिया गया है।

इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। लोग हैरान हैं कि घरेलू प्रताड़ना और रोज़ की मारपीट किस हद तक किसी महिला को अंदर से तोड़ सकती है कि वह खुद ही अपने जीवनसाथी की हत्यारिन बन जाए।

अमेजन का नया 'वेगा ओएस', सैमसंग का एआई स्वास्थ्य फीचर और एप्पल का ऑफलाइन एआई सिस्टम — टेक्नोलॉजी जगत में नवाचार की नई लहर

(जीएनएस)। मुंबई। तकनीकी दुनिया में एक बार फिर बड़ी कंपनियों के बीच नवाचार की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। अमेजन, सैमसंग, एप्पल और ऑप्टोमा ने अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे नए प्रोडक्ट्स और सिस्टम पेश किए हैं जो आने वाले समय में उपभोक्ताओं की डिजिटल जीवनशैली को पूरी तरह बदल सकते हैं।

अमेजन ने अपने लोकप्रिय फायर टीवी स्टिक के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम 'वेगा ओएस' लॉन्च किया है। यह लिनक्स आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे रिएक्ट नेटिव तकनीक से तैयार किया गया है। कंपनी ने बताया कि यह सिस्टम स्ट्रीमिंग अनुभव को और तेज़, स्थिर और स्मूद बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। फिलहाल इसे 'फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट' पर उपलब्ध कराया गया है, जो कंपनी का सबसे किफायती 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस है। नया वेगा ओएस बेहतर इंटरफेस, तेज़ नेविगेशन और मल्टी-डिवाइस इंटीग्रेशन की सुविधा देता है, जिससे यूज़र्स बिना किसी लैग के ऑनलाइन कंटेंट का आनंद ले सकेंगे।

वहीं, सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी वॉच 8 और अल्ट्रा के साथ एक ऐसा एआई-आधारित स्वास्थ्य फीचर पेश किया है, जो

चिकित्सा तकनीक में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। यह फीचर दिल के दौरे के शुरुआती संकेत पहचानने में सक्षम है और खासकर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन नामक हृदय विकार की निगरानी पर केंद्रित है। स्मार्टवॉच का ईसीजी सेंसर उपयोगकर्ताओं के हृदय की धड़कन में सूक्ष्म परिवर्तन दर्ज कर सकता है और समय रहते खतरे का संकेत दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तकनीक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिन्हें बीमारी के लक्षण स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होते, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा।

इसी क्रम में एप्पल ने अपने नवीनतम iOS 26 अपडेट के साथ एआई फाउंडेशन मॉडल्स फ्रेमवर्क पेश किया है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह पूरी तरह ऑफलाइन काम करती है, यानी यूज़र्स के डेटा को क्लाउड पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एआई सिस्टम टेक्स्ट लिखने, लंबे लेखों या ईमेल का सारांश तैयार करने और उपयोगकर्ता की लेखन शैली के अनुसार सुझाव देने जैसे फीचर्स प्रदान करेगा। एप्पल का दावा है कि यह मॉडल गोपनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए तेज़ और सुरक्षित एआई अनुभव देगा। इसी बीच ऑप्टोमा ने घरेलू मनोरंजन बाजार में नया धमाका करते हुए 'फोटॉन लाइफ सीरीज़' लॉन्च की है, जिसमें PK32 4K 4LED प्रोजेक्टर शामिल है। यह प्रोजेक्टर 150 इंच की अल्ट्रा एचडी इमेज प्रोजेक्ट कर सकता है, जिससे घर पर सिनेमा जैसा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इसकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया बेहद सरल है और एलईडी तकनीक के कारण इसे लंबे समय तक बिना रखरखाव के इस्तेमाल किया जा सकता है।

तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि इन चारों कंपनियों के नए उत्पाद और फीचर आने वाले महीनों में टेक मार्केट में प्रतिस्पर्धा को और तेज़ करेंगे। जहां अमेजन स्ट्रीमिंग डिवाइस के अनुभव को पुनर्परिभाषित कर रहा है, वहीं सैमसंग और एप्पल स्वास्थ्य और एआई के क्षेत्र में मानवीय सुविधा और सुरक्षा की सीमाएं आगे बढ़ा रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि आने वाला समय उपयोगकर्ता के लिए अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवों का होगा — जहाँ हर डिवाइस न केवल मनोरंजन का साधन बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य, गोपनीयता और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा भी।